संस्थापक – सम्पादक : स्व. श्री महेन्द्रकुमार

कार्यकारी सम्पादक : चिन्मय मिश्र

सप्रेस आलेख : 156 : 2013–14

दिनांक 28–03–2014

प्रकाशनार्थ

फोन एवं फैक्स : (0731) 2401083

सर्वोदय प्रेस सर्विस बुलेटिन

साप्ताहिक सर्वोदय समाचार विचार सेवा

29, संवाद नगर, नवलखा, इंदौर – 452001 (म.प्र.)

E.Mail - indoresps@gmail.com

(इस आलेख का उपयोग तुरंत किया जा सकता है)

मोदी बनाम मोदी अर्थव्यवस्था

✍ आशीष कोठारी

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के विकास के माडल की जमीनी हकीकत को जान लेना आवश्यक है। भारत को विकास की राह पर ले जाने वाला आधुनिक औद्योगिक माडल जितनी विकास दर हमें दे रहा है इससे उपजा प्रदूषण उतना ही हमारी आर्थिक वृद्धि से ले जाता है। आर्थिक रूप से हम ऋणात्मक वृद्धि दर पर है क्योंकि इस प्रक्रिया में होने वाले सामाजिक, सांस्कृति, स्वास्थ्य एवं मानवीय हानियों की हम गणना ही नहीं करते। (कासं.)

नरेंद्र मोदी को एक सामाजिक विभाजक प्रधानमंत्री माने जाने से भी बड़ा डर विकास का उनका ढर्रा है। गोवा में हालिया चुनावी भाषण में मोदी ने घोषणा की कि यदि वे प्रधानमंत्री बने तो राज्य में खनन पुनः प्रारंभ करवा देंगे। (उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि पानी, पर्यावरण एवं लोगों की आजीविका पर पड़ने वाले जबर्दस्त विपरीत प्रभावों की वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन दिया है।)

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके शासनकाल में ऐसे निर्णयों की बाढ़ सी आ गई है जो कि प्रकृति और गरीबों के विपरीत कहे जा सकते हैं। 2500 करोड़ रु. की लागत से नर्मदा नदी में पटेल की प्रतिमा की स्थापना जैसी परियोजनाओं के प्रति लगाव से, उनके द्वारा देश का सर्वोच्च पद संभालने की संभावना और अधिक डर पैदा करती है।

समुदाय, जनआंदोलन एवं गैर सरकारी संगठन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री वीरप्पा मोइली द्वारा खनन, औद्योगिक एवं अधोसंरचना परियोजनाओं को अत्यंत शीघ्रता से स्वीकृति प्रदान करने को लेकर विचलित है। वैसे यूपीए ने पिछले एक दशक मे तकरीबन 2.5 लाख वन भूमि का भू उपयोग बदल दिया था। ऐसे में यदि मोदी अर्थव्यवस्था को छुट्टा छोड़ दिया जाएगा तो व्यापक स्तर पर घटित सामाजिक और पारिस्थितिकीय असंतुलन का पिछला पैमाना भी टूट जाएगा।

शक की दशा में तथाकथित विकास के नाम पर भारत जैसे देश में पर्यावरण की बलि चढ़ाना क्या न्यायोचित है? इसके जवाब हेतु विकास के वर्तमान माडल के सबसे आक्रामक पैरोकार विश्वबैंक की नवीनतम रिपोर्ट को पढ़ लेना चाहिए। इसमें अनुमान लगाया गया है कि भारत में पर्यावरणीय नुकसान से होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों की वजह से आर्थिक वृद्धि दर में 5.7 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत की वृद्धि दर भी इससे अधिक नहीं रही है। बैंक के अनुसार इसमें विस्थापन, बेदखली, बीमारी, समयपूर्ण मृत्यु, कुपोषण और रोजगार की हानि जैसे डरावने व अपूरणीय सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव भी छुपे हुए हैं।

गुजरात इसका बेहतरीन उदाहरण है। श्रम एवं पर्यावरण कार्यकर्त्ता रोहित प्रजापति एवं तृप्ति शाह ने मोदी अर्थव्यवस्था के पारिस्थितिकीय एवं सामाजिक प्रभावों को बेनकाब किया है। सरकार के अपने ही रिकार्डों का उनका विश्लेषण नए रोजगार सृजन, गंभीर अल्प भुगतान, उद्योगों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध कराने हेतु किसानों की जानबूझकर बेदखली और जबरिया अधिग्रहण के अत्यंत गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। गुजरात में भारत की 30 प्रतिशत खतरनाक दुर्घटना वाले उद्योग स्थापित हैं और यहां 4500 खतरनाक रसायन कारखाने भी मौजूद हैं।

इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि सन्

❖ श्री आशीष कोठारी प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। सम्प्रति कल्पवृक्ष संस्था से जुड़े हैं।

2009, 2011 और 2013 में तैयार भारत के गंभीर प्रदूषित इलाकों की सूची में गुजरात के अंकलेसरिया और वापी सबसे ऊंचे स्थान पर थे। इसके बावजूद यहां कोई आकस्मिक आपदा प्रबंधन योजना नहीं है। इतना ही नहीं गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी (मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष हैं) के पास उद्योगों की संपूर्ण जानकारी तक नहीं है। इसके बावजूद मोदी के कार्यकुशल प्रशासन गुणगान किया जाता है।

वहीं तथाकथित गुजरात चमत्कार के मध्य राज्य में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बदहाली के प्रमाण भी जगजाहिर हैं। यही उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने वालों (ड्रॉप आउट) की दर असाधारण रूप से अधिक यानि 58 प्रतिशत है। यह विशेषकर आदिवासियों 78 प्रतिशत एवं दलितों में 65 प्रतिशत तक हैं। इतना ही स्वास्थ्य सूचांकांकों में भी स्थिति अत्यंत दयनीय है। यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि यहां शिक्षा व स्वास्थ्य पर किया जाने वाला खर्च राष्ट्रीय औसत से कम है। इसमें इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया है कि खराब स्वास्थ्य की वजह रसायन एवं प्रदूषण के अन्य प्रकार हैं।

मोदी के 'विकासवाद' में अडानी जैसे कारपोरेट्स को भूमि एवं पानी की उपलब्धता हेतु सभी कायदे कानून अहंकारपूर्वक दरकिनार कर दिए जाते हैं। पटेल की मूर्ति संबंधी उनकी योजना भी अजीब सी महसूस होती है। यह विश्व की सबसे बड़ी ही नहीं बल्कि संभवतः सबसे खर्चीली पर्यटन योजना भी है? इससे जुड़ा पर्यावरण, 70 गांवों की भूमि, पानी व अन्य संसाधन राज्य ले लेगा। इसमें एक बड़ा हिस्सा आदिवासी कृषि भूमि है और राज्य सरकार इस भूमि के अधिग्रहण या इसे गैर कृषि घोषित करने हेतु केवड़िया क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया है। इसके अलावा कल्पसर परियोजना भी है। इसके अंतर्गत मोदी खंबात की खाड़ी में बांध बनाकर राज्य की जल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु साफ पानी का विश्व का सबसे बड़ा जलाशय निर्मित करना चाहते हैं। इस तरह की विशाल सामाजिक व पारिस्थितिकीय लागत वाली परियोजनाएं कच्छ और सौराष्ट्र के लोगों द्वारा बताई गई काफी सस्ती, अधिक टिकाऊ और लोकतांत्रिक ढंग से प्रबंधित जल सुरक्षा विकल्पों की अनदेखी करती है।

इस बात की कोई संभावना नहीं है कि मोदी दिल्ली की कुर्सी पर बैठने के बाद विकास दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन लाएंगे। वह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को आदेश देंगे कि वह वीरप्पा मोइली द्वारा प्रत्येक परियोजना की राह में आने वाली रुकावट को हटाने जैसा अच्छा कार्य करें। वे तो सन् 1980 एवं 90 के दशक में लोगों के संघर्ष के माध्यम से जो कुछ पर्यावरण कानून इसमें आड़े आते हैं, उनके विलोपन का प्रयास करेंगे। यह प्रवृत्ति भारत में वैश्वीकरण के प्रवेश के साथ ही प्रारंभ हो गई थी और मोदी इसे और आगे ले जाएंगे।

गुजरात के कार्यकर्ताओं ने बताया है कि वहां असहनशीलता और तानाशाही का वातावरण है जो असहमति को हतोत्साहित करता है। जब ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने 31 अक्टूबर 2013 को मोदी की नर्मदा में होने वाले पटेल प्रतिमा शिलान्यास समारोह का शांतिपूर्ण विरोध करने की घोषणा की तो उन्हें बलात् रोका गया और कहा गया कि मुख्यमंत्री के वहां रहते कोई आवाज नहीं उठाएगा। इसके पहले सन् 2013 में ही भावनगर जिले में प्रस्तावित परमाणु बिजली संयंत्र हेतु जनसुनवाई भी भारी पुलिस बंदोबस्त, भय एवं आतंक के वातावरण में की गई थी। निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गांवों एवं शहरों में मछुआरों, किसानों, आदिवासियों एवं हाशिए पर पड़े लोगों के विरोध की या तो अनदेखी की गई या उसे कठोरता से कुचल दिया गया। डर है कि सूचना का अधिकार जैसे कानूनों को लागू संघर्ष से प्रधानमंत्री के नाते मोदी कठोरता से निपटेंगे।

मोदी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर सबसे ज्यादा प्रसन्न संभवतः कारपोरेट क्षेत्र एवं ऊपर की ओर छलांग मारता उच्च मध्य आय वर्ग है। उनके लिए न्याय के लोगों के संघर्ष, गरीबों द्वारा विस्थापन एवं भूमि अधिग्रहण का प्रतिकार करने वाले संघर्ष और पर्यावरणीय सक्रियता कमोवेश समृद्धि के उनके सपनों में रुकावट डालते हैं। इस वैश्विक वृद्धि मॉडल ने बता दिया है कि भारत के औपचारिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि दर कमोवेश शून्य रही है और इसमें भावी पीढ़ी के स्वस्थ एवं बेहतर जीवनस्तर को तवज्जो नहीं दी जाती है। दुर्भाग्यवश, यह संभावना बनी हुई है कि अन्य वर्गों के लोग भी बड़ी संख्या में मोदी तो मत देते हुए उन 10 प्रतिशत भारतीयों में स्थान पाने का सपना देखेंगे जिनके पास आज भारत की 53 प्रतिशत संपत्ति का स्वामित्व है। यह एक बड़ी भूल होगी, क्योंकि भले ही कोई सत्ता में आए इस तरह के विकास मॉडल में ऐसे स्वप्न दिवास्वप्न ही बने रहते हैं। (सप्रेस)

नोट : लेख का उपयोग होने पर कतरन एवं पारिश्रमिक की राशि 'सर्वोदय प्रेस सर्विस' के नाम भेजें।